SHRI SHYAMAL CHAKRABORTY: Sir, my question is: From where will the State Government get this huge fund? I would like to know whether the Central Government is prepared to spend this huge sum for rapid transport system and the metro transport system.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, apart from the general question of finance, although it is a State matter, as I said before, we are, through our Jwaharlal Nehru National Urban Renewal Mission and the Viability Gap Funding by the Finance Ministry, making lots of money available. It is for the State Governments to avail of these avenues.

श्री उदय प्रताप सिंह: सभापति जी, मेरा एक सीधा सा सवाल हैं कि इतनी मुश्किल हो रही हैं कि उसे स्टेट का विषय कहकर हम उससे बच नही सकते हैं। बड़े शहरों का हाल यह हैं कि वहां जाम लगते हैं। चीन और जापान के कई शहरों में उन्होंने साइकिलों की व्यवस्था बना दी हैं, इससे तीन लाभ होते हैं- इससे pollution कम होता हैं, पेट्रोल बचता हैं और यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि इस congestion को कम करने के लिए क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनाएगी जिसमें इस तरह के side tracks बनाए जाएं, जहां लोग साइकिलों से जा सकें? क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि थोड़ी- थोड़ी दूर के लिए जो अफसर वगैरह जाया करते हैं, उनके लिए कुछ ऐसे नियम बनाएगी कि अगर वे थोड़ी देर के लिए जाएं, तो साइकिल से चले जाएं या पैदल चले जाएं? हालत यह हैं कि एक आदमी चलता हैं और पूरा जाम हो जाता हैं। आपको कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए, अगर ऐसी योजना नही बनेगी, तो इस समस्या से निजत मिलने वाली नही हैं।

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, I am in total agreement with the hon. Member. Our Government is exactly thinking on these lines. We are pleading with the State Governments to think of a comprehensive mobility plan. We are ourselves financing the studies of these plans in every city and giving subsidy up to 40 per cent. In fact, we are, at the moment, thinking of enhancing the assistance for studies from 40 per cent to 80 per cent, and in BRTS and other schemes we are insisting upon separate tracks both for cyclists and pedestrians. I couldnt agree with the Member more.

श्री कलराज मिश्र: सभापति जी, मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा, आपने कहा हैं कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टाम प्रोजेक्ट शुरू किया हैं, जिसमें अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, इंदौर,भोपल, पुणे, चिंचवाड़, विजयवाड़ा, विशखापतनम तथा जयपुर स्वीकृत हो चुका हैं, यह कब से प्रारंभ होगी? क्या इसी 'जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन' के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ जैसे जो बड़े शहर हैं, यहां के लिए भी इस प्रकार की योजना रखने की कोशिश की गई हैं?

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, we are more than willing to finance the schemes in all the cities suggested by the hon. Member. The initiative has to be taken by the State Government. I do not want the hon. Member to get away with an impression that we are trying to escape the responsibility by referring to State's initiative. We are here to finance the schemes. But the initiative has to be taken by the State Governments. We are ready to finance such schemes in all the major cities.

यमुना कार्य योजना

***367। श्रीमती सुषमा स्वराज:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि यमुना विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में से एक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य योजना की तरह कोई यमुना कार्य योजना भी तैयार की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटाल पर रखा हैं।

विवरण

(क) से (ग) केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वजीराबाद और ओखला के बीच पड़ने वाला यमुना नदी का क्षेत्र समूचे देश की प्रमुख नदियों के प्रदुषित क्षेत्रों में से एक हैं। यह दिल्ली में ओखला से लेकर उ. प्र. में इटावा तक भी प्रदूषित हैं। तथापि यमुना नदी के जल की गुणवत्ता हरियाणा के अधिकांश स्थलों तथा उ. प्र. में इटावा के डाउनस्ट्रीम में निर्धारित सीमा में हैं।

भारत सरकार ने यमुना नदी का प्रदूषण कम करने के लिए जापान बैक फार इंटरनेशन कोआपरेशन, जापान सरकार की सहायता से चरणबद्ध रूप से यमुना कार्य योजना प्रारंभ की हैं। यमुना कार्य योजना चरण-I 1993 में शुरू किया गया था और इसे फरवरी, 2003 में बंद घोषित किया गया था। यमुना कार्य योजना का दूसरा चरण दिसंबर, 2004 में शुरू किया गया था और इसके पूरा होने की अवधि 5 वर्ष रखी गई थी।

यमुना कार्य योजना चरण-I में तीन राज्यों अर्थात उ. प्र., हरियाणा और दिल्ली के 21 शहरों में 682 करोड़ रू. की लागत से अन्य कार्यों के अलावा सीवेज का अवरोधन और मार्ग परिवर्तन, सीवेज शोधन सयंत्रों की स्थापना, अल्प लागत शौचालय बनाना, शवदाहगृह बनाना, नदी मुहानों का विकास करना तथा जनभागीदारी और जागरुकता आदि से सबंधित कुल 269 प्रदुषण उपशमन कार्य शुरू किए गए थे। इस चरण के अंतर्गत 753.25 मिलियन लीटर प्रतिदिन की शोघन क्षमता वाले कुल 38 सीवेज शोधन सयंत्र स्थापति किए गए हैं।

यमुना कार्य योजना चरण-II को राज्यों द्वारा यथा प्राथमिकीकृत यमुना नदी के प्रदुषण उपशमन कार्य शुरू करने के लिए तैयार किया गया था। इस चरण में (i) दिल्ली में सीवेज शोधन सयंत्रों की स्थापना। पुनः स्थापना तथा ट्रंक सीवरों का पुनः स्थापना/ उन्हें बदलना, (ii) आगरा, उ. प्र. में सीवेज शोधन सयंत्रों की स्थापना, सीवर लाइनें बिछाना और मुख्य और ऊंची लाइन को उठाना और, (iii) हरियाणा के छः शहरों में सीवर लाइनें बिछाना। इस चरण की अनुमानित लागत 624 करोड़ रु. हैं। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत 24 स्कीमों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को अब तक 82.66 करोड़ रू. की राशि जारी की गई हैं। ये स्कीमें प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। उपर्युक्त के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने अपने योजना कोष से बड़े पैमाने पर सीवरेज, नॉन सीवरेज और सीवेज शोधन कार्य भी आरंभ किए हैं।

Yamuna Action Plan

†*367. SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Yamuna is one of the most polluted rivers in the world;

(b) if so, whether any action plan for Yamuna has been prepared on the lines of Ganga Action Plan; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI NAMO NARAIN MEENA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) According to Central Pollution Control Board (CPCB), the stretch of river Yamuna between Wazirabad and Okhla in Delhi is among the most polluted stretches of major rivers across the country. It is also polluted in the stretch from Okhla in Delhi to

† Original notice of the question was received in Hindi.

Etawah in U.P. However, the water quality of river Yamuna is within prescribed limits in majority of the locations in Haryana and downstream of Etawah in U.P.

The Government of India has undertaken Yamuna Action Plan (YAP) for abatement of pollution of river Yamuna with the assistance from Japan Bank for International Cooperation, Government of Japan in a phased manner. YAP Phase-I was launched in 1993 and declared closed in February, 2003. The second phase of YAP was started in December, 2004 with the completion period of 5 years.

A total of 269 pollution abatement works pertaining to interception and diversion of sewage, installation of Sewage Treatment Plants (STPs), Low Cost Sanitation, Crematoria, River Front Development, Public Participation and Awareness among others, were taken up in YAP Phase-I at a cost of Rs. 682 crore in 21 towns in the three States of U.P, Haryana and Delhi. A total of 38 STPs having a treatment capacity of 753.25 million litres per day (mid) have been created under this phase.

YAP Phase-II was formulated to take up other pollution abatement works of the river Yamuna, as prioritized by the States. This phase includes, (i) installation/rehabilitation of STPs and rehabilitation/replacement of trunk sewers in Delhi, (ii) installation of STPs, laying of sewer lines and rising mains in Agra, Uttar Pradesh, and (iii) laying of sewer lines in six towns of Haryana. The estimated cost of this phase is Rs. 624 crores. An amount of Rs. 82.66 crores has been released to the State Governments for completion of 24 schemes sanctioned under this Plan so far. These schemes are under various stages of progress. In addition to the above, the Government of NCT of Delhi has also taken up large scale sewerage, non-sewerage and sewage treatment works out of its own Plan funds.

श्रीमती सुषमा स्वराजः मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत उत्तर मेरे प्रश्न का दिया हैं। मै मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि आपने यह तो सब बता दिया कि यमुना को स्वच्छ करने के लिए दो चरणों में कार्य योजना चली हैं। यह भी बता दिया कि इसमें कितनी राशि खर्च हुई हैं, यह भी बता दिया कि कितने कार्य किए गए हैं, लेकिन यह आपने नही बताया कि प्रदूषण के स्तर में कितनी गिरावट आई हैं। मै आपसे केवल यह जानना चाहती हूं कि 1993 में यह कार्य योजना प्रारंभ होने से पहले यमुना का प्रदूषण स्तर क्या था और 2003 में पहला चरण समाप्त होने के बाद प्रदूषण स्तर क्या हैं? दूसरा चरण शुरू होने से पहले प्रदूषण स्तर क्या था और आज तीन वर्ष पूरे हो जाने के बाद प्रदूषण स्तर क्या हैं?

श्री नमो नारायण मीणा: सर, इस सबंध में माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि River conservation is an on-going activity, दूसरा, Water is a state subject, now I am telling कि जब यमुना का conservation का काम प्रारंभ किया गया था, उसके बाद pollution load भी लगातार बढ़ता चला गया। आज की तारीख में यमुना का जो pollution load हैं, वह 4500 mld हैं, उससे पहले यमुना का pollution load करीब 2500 mld के आसपास था। इस तरह से pollution load बढ़ गया हैं। मै यह एडमिट करने को तैयार हूं कि जितने desire improvement होने चाहिए थे, वह नही हुए हैं। चूंकि जनसंख्या बढ़ रही हैं पोल्यूशन लोड बढ़ रहा हैं ...(व्यवधान)... **श्रीमती सुषमा स्वराजः** सर, मुझे लंबा जवाब नही चाहिए।

MR. CHAIRMAN: You have a second supplementary.

श्रीमती सुषमा स्वराजः सर, समय समाप्त हो जाएगा। वह कह रहे हैं कि on-going process हैं, **मैं** उनका उत्तर पढ़कर सुनाना चाहती हूं ,"1993 में कार्य योजना का चरण-I शुरू किया गया और जो फरवरी, 2003 में

बंद कर दिया गया" , इसलिए मै यह जानना चाह रही हूं कि यह जो चरण दस साल तक चल कर समाप्त हो गया, यह on-going नही हैं, 1993 में क्या था और 2003 में जब बंद हुआ तो कितने पर बंद हुआ? कितना कम हुआ? 682 करोड़ रूपए खर्च हुआ, दस साल तक योजना चली और 2500 से बढ़कर 4500 हो गया, यह on-going process नही हैं, यह उनका उत्तर हैं, इसलिए हमको यह जवाब दिलवाइए कि 1993 में कितना था, दस साल बाद जब 682 करोड़ रूपए खर्च हो गया तो कितना कम हुआ?

MR. CHAIRMAN: Please don't interrupt.

श्री नमो नारायण मीणा: सर, जहां तक आप specific पूछना चाहती हैं कि क्या हुआ हैं, उसके बाद में कुछ improvement हुए हैं, अगर वह detail चाहती हैं तो वह मै आपको बताता हूं ...(व्यवधान)... ।

MR. CHAIRMAN: Please don't interrupt.

श्री दिग्विजय सिंह: सर, लेवल पूछां जा रहा हैं, यह गलत जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)... ।

श्री दिग्विजय सिंह: लेवल बताइए कि कितना हैं, कितना बढ़ और कितना घटा ...(व्यवधान)... ।

श्रीमती सुषमा स्वराज: 1993 में क्या था, जब 682 करोड़ रूपए खर्च हो गया तो क्या हुआ?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Special Purpose Vehicle for coal

•363. SHRI JESUDASU SEELAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government gave its approval to the Special Purpose Vehicle (SPV) formed by the steel companies to acquire coal properties abroad to meet their needs;

(b) whether the proposed SPV would have an authorised capital base of rupees ten thousand, crore and a paid up capital of three thousand five hundred crore;

(c) whether Steel Authority of India Limited, Rashtriya Ispat Nigam Limited, Coal India Limited, National Mineral Development Corporation and NTPC have joined hands to acquire coal properties abroad especially in Australia and Canada; and

(d) if so, to what extent it would be helpful in overcoming the coal shortage in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI SANTOSH BAGRODIA): (a) The Government has approved formation of a Special Purpose Vehicle (SPV) for securing metallurgical coal and thermal coal assets from overseas by the Public Sector Undertakings (PSUs) namely, M/s Steel Authority of India Ltd. (SAIL), M/s Rashtriya Ispat Nigam Ltd. (RINL), M/s Coal India Limited (CIL), M/s National Mineral Development Corporation (NMDC) and M/s National Thermal Power Corporation Ltd. (NTPC).

(b) Yes, Sir.

(c) The above mentioned PSUs have come together to form the proposed SPV for acquiring metallurgical coal and thermal coal properties overseas including Australia and Canada.

(d) The proposed SPV aims to supply about 5 Million Tonnes of coal per annum by the year 20011-12, to that extent it would result in reducing the coal shortage in the country.